

>

Title: Regarding jobs for EWS Quota in Delhi University and non-payment of salaries to the Ad-hoc Teachers of the Universities.

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लाना चाहता हूँ।

जैसा कि सर्वविदित है कि दिल्ली विश्वविद्यालय भारत की प्रीमियर संस्थाओं में से एक है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की असंवेदनशीलता के कारण पिछले कुछ वर्षों से यह बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। सन् 2006 से अभी तक विश्वविद्यालय में नए शिक्षकों की बहाली लंबित है। लगभग 8 हजार शिक्षक तदर्थ आधार पर 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं।

महोदय, सन् 2019 में माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस कोटा के कार्यान्वयन में कुछ विसंगतियों के कारण सारी सीटें अभी तक खाली पड़ी हैं। मंत्रालय द्वारा 5 दिसम्बर, 2019 को दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अराजकता के कारण एक वर्ष तक लगातार लगन के साथ काम करने के बाद शिक्षकगण अपने वेतन के लिए दर-दर की ठोकें खा रहे हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय और यूजीसी ने 15 महीने बाद भी आज तक अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया और एक-दूसरे पर आरोपण करके शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

जहां तदर्थ शिक्षकों के मामले में मंत्रालय के दिशा-निर्देश को महाविद्यालय ने अविलंब पालन कर लिया और वहीं विश्वविद्यालय इन्हें दरकिनार कर स्वायत्ता

का राग अलाप रहा है । परिणामस्वरूप साल भर सेवा देने के बावजूद कुछ तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिला । कई वर्षों तक सेवा देने के बाद कई शिक्षक आज दो वक्त के भोजन को मोहताज हो गए हैं । इसके अलावा विश्वविद्यालय में अनियमितता का यह आलम है कि जहां उसी विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में सभी शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के वेतनमान मिल चुके हैं, वहीं विश्वविद्यालय में तदर्थ शिक्षकों को अभी तक यह नहीं मिला है ।

सभापति जी, जहां शिक्षक समाज का आईना होता है, वहीं विद्यार्थी देश का भविष्य होता है । आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उचित कार्रवाई करके दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें ।